MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House standsabjourned ii!I '2 P. K.

The House then abjourned fur lunch ai nine mmutes past cme of the clock.

'Ihe. House reassembled after lunch at two of the. clock. MR. DEPUTY CHAIRMAN' in the Chair.

RESOLUTION *RE* CONTINUANCE OFPROCLAMATION UNDER ARTICLE 356OF THE CONSTITUTION IN RELATIONTO THE STATE OFGUJARAT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIES/™ *vfatm* S 3<m53iH$^{smu\ Fl}$ "' MOHSIN): Sir, I beff t" move th^{e} following Resolution :

> 'That this House approves the continuance in lone ,4' the Proclamation issued by the Ptesidem on the Kith May, 1971, under article 3o(> of the Constitution, in relation tn the. State of Gujarat, for a furthur period of six months with effect from the 21st Decent her. 1971."

Sir, Members of this House may recall thai ihe presidential Proclamation under articl ol" the Constitution was issued on 13th May, 1971 in respeei ofithc State of Gujarat. Tt was approved by the Rajya Sabha on 31st May, 1971 and by the Lok Sabha on 21stjttne, 1971. In accordance with clause (4) of article 2~)i> the proclamation will remain in force only up to 20th December, 1971 unless ii is extended by both the Houses of Parliament. Sir, the House may he aware thai ihe Election Commission liad undertaken intensive revision of electoral rules including that of Gujaral and ihe revision has been j ust completed bu1 *a* special revision has been undertaken by the Election Commission of four Assembij Constituencies in Gujaral and thai is likely to be completed very soon. The Government of India proposes io hold the elections in the State of Gujarat in the third week of February 1972, but much before that the Presidential Proclamation will expire ou 20tb December, 1971 and hence I have to n this Resolution befor* the House. I hope the House will give approval to this Resolution-

The question was proposed.

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता (गुजरात): माननीय उपाध्यक्ष जी, गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि हम यह समझते थे कि यह प्रस्ताव फिर लाने की जरूरत नहीं होगी। मगर 6 महीने हो गये और यह प्रस्ताव फिर से लाना पड़ा। हमारे माननीय मिनिस्टर महोदय ने बताया कि फरवरी में इलेक्शन होगा।

आज हमारी एक दिक्कत है। हमारे देश में हमारे जो टैक्सेज हैं, वे बढ़ रहे हैं और अभी भी दो तीन दिन पहले थोड़े टैक्सेज गुजरात में बढ़ाये गये हैं। आदमी की आमदनी जितनी होती है उतनी ही रहती है, इसलिए आज जीवन संग्राम हमारा बड़ा कठिन हो रहा है और हम देखते हैं कि जो गुजरात की गरीब प्रजा है, जो गुजरात का मिडिल क्लास है, उसके जीने के लिए एक बड़ा भारी प्रश्न पैदा हो गया है। हम सोचते हैं कि हम समाजवादी समाज की रचना करेंगे और गरीबी दूर करेंगे, मगर आज जो टैक्सेज बढ़ रहे हैं उसी से न गरीबी दूर हो सकती है और न समाजवादी समाज की रचना हो सकती है। टैक्सेज बढ़ने से हम जहां थे वहीं हैं और इतना ही नहीं, टैक्सेज बढ़ने से आज हमारी स्थिति बिलकुल चिन्ताजनक है। और आज युद्ध के कारण लोगों के दिल में एक तड़प है। इसके साथ ही जो एक बड़ी चिन्ता है, वह चिन्ता यह है कि हमारा जो मार्केट है वह आज स्लो हो गया है, इसलिए जो धंधा था, जो व्यापार था, जो व्यवसाय था, उसमें बहुत कमी आ गयी है और इसलिए आज जो मनी मार्केट है वह भी बहुत तंग हो रहा है। यह हमारी परिस्थिति है और इसमें आज हमारी बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। गुजरात की आज यही दशा है। इस साल वहां बारिश ठीक हुई, इसलिए जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, वहां की फसल कुछ अच्छी हुई है और अच्छी फसल होने के कारण ही हमको वहां कुछ सांस लेने का समय मिला है। किन्तु सारे स्टेट में अच्छी फसल नहीं हुई। कुछ ऐसे भी जिले हैं कि जहां फसल बहुत

खराब हुई है और वहां के लिए आज से ही हम को चिन्ता करनी चाहिए। हमारे यहां गुजरात की रिपोर्ट में बताया गया है कि 'राइट टु वर्क' होना चाहिए हर एक को और उसके लिए जो आपने अम्बर चर्खे का काम लोगों को दिया है वह ठीक है, लेकिन जहां लोगो के पास कोई आमदनी नहीं है। जहां लोगों के पास व्यवसाय नहीं है और जहां फसल भी अच्छी नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए 'राइट टु लिव' की बात ध्यान में रख कर कोई बात करनी चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं और मैं प्रार्थना करती हूं कि इस राष्ट्रपति शासन के बाद कोई भी पापुलर गवर्नमेंट आये, उसे 'राइट टु लिव' की बात ध्यान में रख कर लोगों को रोजी-रोटी देनी चाहिए और उसका प्रबंध करना चाहिए।

एक बड़ी बात यह होती है कि हम अलग-अलग स्कीम्स रखते हैं, पैदा करते हैं और फिर सोचते है कि यह ऐसे चलेंगी, यह ऐसे चलेंगी, मगर एक बात हम नहीं सोचते कि आज हमारी आमदनी क्या है, हमारे ऊपर टैक्सेज कितने हैं और हमारे ऊपर जो वेतन का खर्च है वह क्या है। अभी मैं सोच रही थी कि हमारे देश में करीब हर साल हमारे कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है, उनका मंहगाई भत्ता बढ़ रहा है। वह उसके लिए मांग करते हैं, और ठीक ही है कि गवर्नमेंट उसको देती है। यह ठीक है, लेकिन उनके साथ दूसरे जो लोग है देश में, जिनकी आमदनी अनिश्चित है, जिनकी कोई निश्चित आमदनी नहीं है, उनकी आमदनी बढ़ती नहीं, उनका तो खर्च ही बढ़ता है। इसलिए आज यह परिस्थिति है कि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को जितनी महंगाई लगती है, उनके सर्विस क्लास को जितनी मंहगाई लगती है, उतनी ही महंगाई और दूसरे लोगों को भी लगती है, उनके लिए सरकार क्या करती है? इसलिए आज हमारी परिस्थिति बहुत ही कठिन है। आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं, जिनको आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स बोलते हैं और जो रजिस्टर्ड हैं उनकी ग्रान्ट की जो सीलिंग है वह बढ़ी नहीं, मगर उनके लिए गवर्नमेंट का परिपत्र हमेशा जाता है कि उनकी पगार और उनके नौकरों की मंहगाई बढ़नी चाहिए और अगर वह महंगाई नहीं बढ़ाते हैं तो उनको ग्रान्ट भी नहीं मिलती है। तो जब तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और जब आप उसे बढ़ाने को उनको कहते हैं तो उसके साथ ही जो ग्रान्ट की सीलिंग है वह भी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी तरफ गवर्नमेंट कभी देखती नहीं। वह तो बोलते हैं कि उसी वेजेज पर काम करेंगे एक बाजू से यह बोलते हैं और दूसरी बाजू यह होता है। इसलिए क्या होता है कि सभी जगह बड़ी चिन्ता है कि क्या करना है, कैसे चलाना है और क्या नहीं करना है और भी आगे बढ़ते है और हमारे पास जो चित्र हैं वह चित्र हैं कि आमदनी कम है और खर्च बहुत है।

देखिये, इरिगेशन के बारे में भी हमारे लिए बड़ी चिन्ता है। मेजर इरिगेशंस के लिए हम हमेशा बहस करते है कि नर्मदा को करें, यह करें वह करें, मगर जो माइनर इरिगेशन है उसके लिए हमने अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया है।

हमारा जो कोस्टल एरिया है वहां पानी खारा हो रहा है, जो हमारी हरी-भरी जमीन थी, जहां फसल अच्छी होती थी, वहां समुद्र का पानी घुस रहा है और वहां कोई छोटा-मोटा बांध भी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आज इरिगेशन के बारे में बड़ी-बड़ी बात होती है, बड़े-बड़े जलसे होते है। लेकिन जो सचमुच में हमारे किसान लोगों की जरूरियात हैं, उनके लिए हम अभी भी बेखबर है, इससे हम आगे नहीं बढ़े हैं।

दूसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट में बताया है कि फारेस्ट के लिये बहुत काम किया है। ठीक है कि काम किया है, मगर फारेस्ट का अर्थ गिर की सैंक्चुअरी मात्र नहीं है, फारेस्ट के साथ सारे गुजरात का फारेस्ट आता है। जो 9 परसेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं जानती हूं कि गुजरात में फारेस्ट का डिटेरियोरेशन हो रहा है। वहां कोई पानी का प्रबन्ध नहीं है, कोई तालाब नहीं है, नदी जो पड़ोस में से चलती है उसके लिए कोई बांध नहीं है। वहां यह देखने में आया है कि वहां के

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

फारेस्ट सूखे हो रहे हैं । वहां पानी बिलकुल नहीं है । और आज हम बताते हैं कि गिर की सैंकचुअरी जो लायंस के लिए रखी है और जिससे हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं वहां के रहने वालों की क्या परिस्थिति है, वहां के लायंस की क्या परिस्थिति है। वहां पानी का प्रबन्ध है या नहीं, वहां इरिगेशन का प्रबन्ध है या नहीं, उसका कुछ सोचा नहीं । मैं बताना चाहती हूं कि सौराष्ट्र में वरुणा का पोरबन्दर के नजदीक फारेस्ट है उसमें पर्वत-माला पर 13-14 तालाब हैं उसका सारा सब-स्वायल-वाटर सारे फारेस्ट में जाता था, लेकिन आज उसमें कभी पानी नहीं टिकता है, क्योंकि सालों से उसकी रिपेयरिंग नहीं किया है और फोर्थ प्लान में भी उसके लिये कोई ठिकाना नहीं है । आज फारेस्ट का डिमार्केशन भी नहीं पूरा हुआ है । आज बहुत से फारेस्ट्स हैं, जहां की हुकूमत फारेस्ट विभाग में है या वहां हुकूमत रेवेन्यु की है इसका कोई तय नहीं किया है। कभी बोलते हैं कि पंचायत के अधीन है, कभी बोलते हैं कि रेवेन्यु के अधीन है और कभी फारेस्ट वाले बोलते हैं कि हमारे अधीन है । तो यह तय नहीं किया । है तो मेरा ख्याल है कि सारे गुजरात के जो फारेस्ट हैं उसके बारे में सोचना चाहिये और जहां तक हम फारेस्ट्स को अच्छी तरह से नहीं सम्हालेंगे वहां तक जो हमारे यहां हर तीसरे साल अकाल होता है वह होने वाला है । और गिर की सैंनचुअरी के लिए भी कहना चाहती हूं कि सिर्फ सैंनचुअरी के आजू-बाजू दीवार खड़ी करने से लायन्स जिन्दा रहने वाले नहीं हैं, उनके लिए खाने की बड़ी दिक्कत है, आज जो वहां पशु-पालक लोग रहते हैं, उनके पशुओं पर ही वह निर्भर रहते हैं, उनको वह खाते हैं और जिन्दा रहते है और अगर जब उनको दूर हटायेंगे तो लायन्स के खाने के लिए क्या होगा, वह सोचने का एक प्राबलम है। लायन्स को जो हम जिन्दा रखना चाहते हैं । वह लायन्स बिना खाये पिये मर जाएंगे और आज आपको मालूम नहीं होगा कि आज भी जब अकाल आता है, दुष्काल आता है, तो गिर के फारेस्ट में पानी नहीं होता है और कभी-कभी पानी का टैंक्स वहां पर रखना पड़ता है और वह आकर पी लेते हैं ; क्योंकि और कहीं पानी का प्रबन्ध नहीं है । इसी तरह से जब खाने का प्रबन्ध न हो तो लायन्स को जिन्दा रखने के लिये जो हम सोच रहे हैं वह कितना सक्सेसफुल होगा, यह चिन्ता करने की परिस्थिति है ।

दूसरी बात है एनिमल हसबेंडरी की । सिर्फ डेयरी और गौशाला से ही कोई एनिमल हसबेंडरी का प्रचार नहीं होता । सौराष्ट्र कच्छ और नार्थ गुजरात में खेती के बाद कृषि के बाद, जो दूसरा व्यवसाय है वह पशुपालन है, वहां लोग गाय, भैंस और भेड़ सब कुछ रखते हैं, मगर आज उनको बचाने के लिये कोई कायमी तौर से हमारे पास व्यवस्था नहीं है ।

परिणाम यह होता है कि एक भी अकाल की स्थिति आती है तो उसका सामना वह नहीं कर सकते हैं, उनके लिये मैं बार-बार कह चुकी हूं, दूसरी बार दुहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि ग्रास बैंक होना चाहिए, पानी का प्रबन्ध होना चाहिए, दुष्काल में यह टिक सकें, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ।

सबसे बड़ी हमारी चिंता कोस्टल हाइवे की है । मैं यहां पर बार-बार बतला चुकी हूं कि 1,100 मील का हमारा कोस्ट है और उसको मिलाने की और सुधारने की जरूरत है । गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ने 15 करोड़ रु० की मंजूरी दी है, उसमें से 6 करोड़ तो मिल गये हैं, मगर वह 6 करोड़ रुपए से कितनी व्यवस्था हुई है, वह भी देखना चाहिए । बड़ौदा से भावनगर तक का जो रास्ता है उसमें 1 करोड़ रु० खर्चा हो गया है । सोनेकाई और भावनगर के बीच कोई पुल नहीं है, उसके कारण जो 1 करोड़ रु० खर्च करके रास्ता बनाया है वह फिजूल है । उसका कोई उपयोग नहीं और ब्रिज के न होने से वह ऐसे ही बेकार पड़ा है । आज हम नहीं सोचते हैं कि जब 2 ब्रिज हो जाएंगे तो बड़ौदा से भावनगर जाने में 140 किलोमीटर रास्ते की बचत हो जाती है, 140 किलोमीटर नजदीक रास्ता हो जाता है और

अहमदाबाद से भावनगर 40 मील नजदीक आ जाता है। इसलिए जब यह इमरजेन्सी का टाइम है, तब मैं आज भी इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि इस चीज को प्रायरिटी मिलनी चाहिए और जो सारा कोस्टल हाईवे है वह जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए।

इसके अलावा हमारे यहां सारे भारतवर्ष का 60 परसेन्ट नमक पैदा होता है, वह हम गुजराज में पैदा करते हैं। मगर जो साल्ट पोर्ट्स है, जहां साल्ट पकता है, वहां जाने को कोई रास्ता नहीं, इसलिए क्या होता है कि कभी बारिश आती है और कभी उसमें हेर-फेर करना होता है तो बड़ा नुकसान साल्ट बनाने वालों को हो जाता है। साल्ट पर जो उप-कर है वह सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के पास जमा रहता है। तो हमारी मांग है कि जो साल्ट पैदा करने वाली जगहें हैं, वहां जाने के रास्तों में सुधार लाना चाहिए, उनके आने जाने के लिए ट्रान्सपोर्ट की सुविधा हो, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह कर जो भारत सरकार में जमा होता है उसमें से साल्ट इन्डस्ट्री को बढ़ाने के लिए लोन और सब्सिडी देना चाहिए। इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि आल वेदर पोर्ट के लिए जो किया यह हमारी एक बड़ी मांग थी और वह पूरी हो गई, मगर जो विरावल का पोर्ट है उसके लिए खास प्रबंध होना चाहिए, क्यों कि सारे गुजरात में 3 पोर्ट हैं, एक कांडला दूसरा है ओखा और तीसरा है विरावल। तो विरावल का पोर्ट जिससे अच्छा काम कर सके उसके लिए आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि विरावल पोर्ट को फोर्थ प्लान में आल वेदर पोर्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां एक सहूलियत यह भी है कि विरावल के पोर्ट के सुधार के लिए सैन्ड या सिल्ट नहीं है; क्योंकि वहां दरिया की ताकत बहुत अच्छी है, पानी गहरा है और इसलिए खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। आधे से ज्यादा काम तो पुराने स्टेट में हो गया था, अब उसके विकास की आवश्यकता है, इसके सिवाय आज वह फिशिंग पोर्ट भी है। वहां से कितने ही स्टीमर और कन्ट्री क्राफ्ट आते जाते हैं दूसरे प्रदेशों से।

एक बड़ी दिक्कत जो हमारे लिए है, वह मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहां जो डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ है, वहां विरावल और मांगरोल दोनों जगह केले और ओनियन्स की बहुत ज्यादा पैदाइश होती है, लेकिन वह पेरीशेवल है, इसलिए बेकार चला जाता है और बहुत सालों से मैं देखती हूं कि रेलवे आथारिटीज कभी वैगन्स की रेगुलर सप्लाई उसको उठाने के लिए नहीं करती है, इस लिए हमारे यहां की यह जो मुख्य पैदाइश है वह बेकार चली जाती है। आपको जान कर दुःख होगा कि पिछले साल हमारे यहां 3 पैसे का एक किलो ओनियन बेचा गया है और 12 पैसे में एक दर्जन केला, जो कि हमारी एक गमनसीबी है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जैसा कोल्ड स्टोरेज पोटेटोज में लिए पालनपुर में किया गया है, वैसे ही कोल्ड स्टोरेज विरावल में भी बनाना चाहिए। इसकी वजह से हमारे यहां यह कठिनाई पैदा होती है कि जो हमारे यहां पैदायश होती है वह वैगन न मिलने के कारण खराब हो जाती है। रेलवे आथारिटीज की यह जिम्मेदारी है कि जितने वैगनों की वहां के लोगों की जरूरत है उसको वे समय पर दे दें, ताकि उन लोगों का माल बाहर भेजने से खराब न हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि पब्लिक सेक्टर में जितनी भी नौकरियां होती हैं, वे बाहर के लोगों को दी जाती हैं। यहां के लोगों को चपरासी की भी नौकरी नहीं दी जाती हैं और वह भी यहां से भेजे जाते हैं। यहां से बड़े-बड़े लोगों को नौकरी के लिए वहां भेजा जाता है और वहां के लोगों को पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं में नौकरी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोग बेकार रहते हैं। जहां तक टैक्नीशियनों की बात है वह तो आप बाहर के लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जहां तक और कामों का सम्बन्ध है, उसमें आप गुजरात के लोगों को काम दे सकते हैं। आज गुजरात में अनइम्प्लायमेंट बढ़ रहा है और ओ० एन० जी० सी० में भी बाहर के लोग काम करने के लिए आये हैं, इवन पियोन्स फ्राम आउट साइड। वहां पर किसी को नौकरी में नहीं लिया जाता है, वह एक बड़े दुःख

[श्री पुष्पाबेन जनार्दनराम मेहता]

की बात है । जो प्रदेश के रहने वाले हैं वे बेकार रहें और दूसरे लोगों को वहां पर नौकरी करने के लिए भेजा जाता है ।

तीसरी बात मैं रिफाइनरी के बारे में कहना चाहती हूं । वहां पर एक दूसरी रिफाइनरी की जरूरत है । हमको इस बात का वचन दिया गया था कि जो इस समय रिफाइनरी चल रही है उस को बढ़ाया जायेगा, लेकिन उसको बढ़ाने की आज तक कोशिश नहीं की गई है जो कि एक बड़े दुःख की बात है । अब इस समय इस प्रदेश में प्रेजीडेन्ट रूल है तो इस बात का फैसला कर लिया जाना चाहिए कि इस रिफाइनरी को बढ़ाया जायेगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि गिरही में आश्रमशाला नहीं है जिसकी वजह से वहां कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पा रहा है । मेरी मांग यह है कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये । हम बराबर इस बात की मांग कर रहें हैं कि वहां पर आश्रमशाला होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी पूर्ति नहीं की गई है । मैं आशा करती हूं कि इस प्रेजीडेन्ट शासन में वहां पर आश्रमशाला बन जायेगा और जो वहां के लोगों ने आशा लगा रखी है वह पूरी होगी ।

सबसे बड़ी बात यह है कि जूनागढ़ में सैनीटेशन और हैल्थ की बहुत कमी है जिसकी वजह से वहां पर अभी कालरा फैल गया है । वहां पर 81 केसेज कालरा के हो चुके हैं, जिसमें से 10 मर चुके हैं । यह तो एक दिन की रिपोर्ट है । लेकिन बाद में क्या हुआ, यह मालूम नहीं हो सका । इसलिए में यह निवेदन करना चाहती हूं कि प्रेजीडेन्ट रूल में वहां पर लोगों को पीने का पानी की सुविधा मिलनी चाहिये । आजकल जो पानी होता है वह क्लारिनेटेड नहीं होता है । जब तक वहां की जनता को और वहां की गांव की जनता को छना हुआ साफ पानी नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की बीमारी वहां पर होती रहेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिकारी और सरकार इन बातों की ओर ध्यान देंगे ।

मुझे कहना तो बहुत था लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि जो वहां पर प्रेजीडेन्ट का रूल बढ़ाया जा रहा है, उसमें जो छोटी-मोटी दिक्कत जनता को होती रहती है उनको दूर किया जायेगा ।

SHRI SURESH J. DESAI (Gujarat) : Mr, Deputy Chairman, Sir, I rise to support the resolution) moved by my friend, the Deputy Home Minister. Six months is a very small il to judge the merits of any administra-tioi . However, the report which has been circulated shows that a lot of good work has been done. It must be said to tlie credit ol the Governor that not only has he pursued die projects which has been already on the anvil, bin Be has successfully concluded quite a number of diem. The report shows that the State Planning Advisory Board was re-eon-stiluted and a number of working groups were appointed and all of them have submitted their reports by the end of November. It has also fur-ther stated that a mid-term appraisal of the State's resources for the Fourth Plan, carried out recently in consultation with the Planning Commission, has revealed that the State's resources have gone up by Rs.45 crores, from Rs.455 crores to Rs.500 crores. It would, there-fore, be possible to step up the size pf ihe State's Fourth Pian to Rs.500 crores. As against the ariginally approved size of Rs.455 crores. This is,-also a very good achievement. It has further staled that the State has made a remarkable progress in realising some of ihe physical targets of (he Fourth Plan. In foodgrains production, the State has achieved the Fourth Plan larget of 44 Iakh tonnes in ihe second year of the Fourth Plan. The State is now very near to becoming self-sufficient in foodgrains. In oil seeds produc-tion, the Fourth Plan target of 17.78 lakh tonnes has been substantially exceeded in the second year of Ihe Fourth Plan. In Cooperation also du: State has made notable progress. This shows that some oi tlie targets which were to be achieved at Ihe end of the Fourth Plan have already been achieved in the second year of tlie Fourth Plan. It has also further staled that the State-has taken an initiative in evolving the scheme 'Right to Work' Ior which a provision of Rs.2.5 is included in the State's Fourth Plan. Twelve Ambar Charkha Centres have been sanctioned under ihe scheme this year so that even ihe old and infirm whose mobility is seve-rely restricted, can take advantage of the scheme 'Right io Work'. This is also a notable achievement.

As far as Public Works Department is concerned, while discussing the Kadana Reservoir Project the report states that the Dam work is in progress and unless the hydro-electric Project is cleared, there will be bottlenecks in the construction oi the dam work which is a project financed by the International Development Association. The State Gevernment is now informed in October 1971 that the Planning Commission would give clearance in principle to this project very soon. I hope that the Home Ministry would pursue the matter becaus: in this project the International Development Association is also a partner and the Home Ministry should pursue the matter further so that the Planning Commission's approval is granted very soon.

As far as the financial position is concerned, it has been very satisfactory and I must say thai \vc arc proud to mention that Gujarat is one ol' the Few States in the country which have not taken an overdraft from the Reserve Bank. When the Budget estimates were presented in March, 1971, they showed a deficit of Rs.8.25 crores. The Budget was recast and the revised estimates as presented to and passed by Parliament in July, 1971, showed only a small deficit of Rs.1.29 crores. And this is also proposed to be met by the economists in the nondevelopment expenditure.

In the field of industries, mines, power and petroleum also the State has made notable progress. The aluminium complex has been now practically finalised. As a result of the efforts made by the Governor, he was able to persuade the Union Minister for Steel to agree to the formation of a separate company for exploiting the Bauxite Ores in the State through Rs. 130 crores giant aluminium Complex consisting of units for production of alumina, an aluminium smelter and fabrication units. The Government ol India has already been requested to initiate project planning for this aluminium complex. This is also a very notable achievement of the Government of Gujarat.

Further, all the policies of ihe Government of Gujarat have been progressive and quite a lot of progress has been done though a lot of things remain to be done in the field of industry, in the field of shipping and also in the field of adequate power supply. For instance, the output of the basic products and their utilisation by user industries has to be coordinated so that problems regarding excess production or lack of timely and adequate demand are avoided. At present the output of ethylene is expected to be 1.3 lakh tonnes whereas Uncapacity planned fur consumption is 1 lakh tonnes, 30,000 tonnes ' remains to be planned. This opens up prospects for plants manufacturing vinyl chloride and styrene or polystyrene. This is very necessary development and it must be attended to not only by the Government of Gujarat, but something has to be done by the Potroleutn and Chemicals Ministry here at Delhi. The expansion of the Gujarat refinery should be so planned and execute as to reach a capacity of 10 million tons. It can then serve as a centre both for processing crude oil obtained locally .es also from our off-shore fields and from abroad.

Another important thing which should be done very soon is the supply of adequate electric power at reasonable cost. In fact the per capita consumption of power in Gujarat is already-very low. As compared io other Stales the per capita comumption in Gujarat is very low. In Delhi it is 273 KWH, in Punjab 159 KWH, in Maharashtra 153 KWH and in Gujarat il is only 135 KWH. The cost of electric power in Gujarat is also very high. This hampers development of industries there. If we compare the cost of power per KWH, il comes io 2.50 paise in Maharashtra under Tata installation and under other installations it is 3 paise ; in Punjab it is 2 paise : in Bihar it is 4 paise : in West I it is 1-paise ; in Tamil Nadu it is 4 paise ; in Madhya Pradesh it is 4.30 paise and in Gujarat it, comes to 5.80 p»isc. If the price of RFO is raised as demanded by the Oil nnd Natural Gas Commission, then the cost will rise to 9 paise per KWH. It will be a great impediment to the development of industries in Gujarat. There is no reason why iherc should not be a uniform electric power tariff ni all over the country. Just like cement, sugar or peper has a uniform price, why not elcctrii iiy also '.' There is no reason why there should not be a uniform price in the case of electricity ? Then only the industrial development of an enterprising State like Gujarat can be fully achir\ ed.

As far as atomic power station is concerned, we understand that already the survey work is done and a site has practically been selected in Saurashtra, We hope that progress in this case will be speedy and accelerated.

[Shri Suresh J. Desai]

There is one more thing to which I would like to refer. And that is about the Port Narmada. The construction and development of a major all-weather, alon-side berthing port at a site near the mouth of River Narmada must be undertaken at the earliest. Already commercial organisations such as the Chambers of Commerce in Gujarat have represented to the government about the construction of tlie port. The location is ideal because the wind, wave and other marine conditions arc most favourable for navigation, etc. An oil port can also be established with close proximity to Gujarat refinery, our off-shore fields and major foreign sources of imported crude. Nowadays tankers are about 2 J to 3 lakh tonnes, but any tankers of 60,000 to 80,000 tonnes can be brought if this port is constructed at the mouth of River Narmada and it should be an all-weather port. The Indian Institute of foreign Trade has already carried out a survey and they have made an assessment of a conservative nature that the hitcrland would provide a traffic of over 3 million tonnes in the initial stage. This is a very hopeful development and if this pott can be developed it wil! not only help the backward distiict of Broach and other parts of Gujarat, but it will also open up the big hinterland behind this port which extends up to Madhya Pradesh. With these words, Sir, I hope the remarks I made will receive the attention of the Home Minister and with these words, Sir, I support the Resolution moved by the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Patel.

श्री देवदत्त कुमार कीकाभाई पटेल (गुजरात): उपसभापति जी, जिन परिस्थितियों में गुजरात के अन्दर राष्ट्रपति शासन जारी किया गया उन परिस्थितियों में वह उचित था। पक्षान्तरण की प्रवृत्तियां इतनी तेज थीं कि उस समय किसी भी पक्ष की कोई स्थिर सरकार बने ऐसी कोई सम्भावना थी नहीं, इसलिये राष्ट्रपति शासन जो 13 मई, 1971 ई० के दिन से लागू किया गया, वह राष्ट्रपति का जो कदम था वह सही था।

श्रीमन्, इस संकल्प के ऊपर बोलते समय मुझे गुजरात की एक-पंचमांश यर्थात् 22 प्रतिशत के करीब जो जनता है, उनकी जो समस्यायें हैं, उनके बारे में कुछ कहना है। यह बड़े अफसोस की बात है कि गुजरात में इतने साल से कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इस शासन काल के दर्मियान इतनी बड़ी आबादी की ओर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान दिया गया नहीं। मैं आरोप लगाऊंगा कि राज्यकर्त्ता पक्ष ने केवल पिछड़ी हुई जातियों का राज्य-शोषण किया वैसे तो आर्थिक शोषण सदियों से उनका होता रहा, लेकिन आजादी के बाद एक राष्ट्रीय-शोषण होता रहा। उनके जो संविधान के अन्दर हक प्रतिष्ठापित किये गये हैं उनका गम्भीरता से पालन गुजरात के अन्दर हमारे देश में ठीक ढंग से हुआ नही, यहां तक कि जो सुरक्षित स्थान उनके हैं वहां से भी उनको येनकेन प्रकारेण हाटाया जाता है। आज भी गुजरात में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें शायद ही एक या दो प्रतिशत इन पिछड़ी हुई जातियों के लोग होंगे। हम दावा करते हैं कि समाजवाद लायेंगे, गरीबों को आगे लायेंगे, इस देश के जो आदिवासी हैं, इस देश के जो प्रथम मूल निवासी है उनको आगे लाने की हम बड़ी-बड़ी घोषणायें करते हैं। लेकिन संविधान में जो सुविधायें दी हैं वह भी उनको नहीं देते हैं और जो सुरक्षित स्थान है उन पर तक उनको नहीं रखना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है कि जहां पर भी मैं कांफ्रेंस में गया वहां भो यही आवाज हमको सुनने में आई, हर एक जगह पर यह सावल है। फिर भी राष्ट्रपति शासनकाल के अन्दर गवर्नर महोदय ने दो-एक कदम ऐसे उठाये हैं; जिनकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। 23 साल के बाद राष्ट्रपति शासनकाल के अन्दर ये दो कदम ऐसे उठाये गये जिसके लिये मुझे आनन्द है, एक तो रूरल हाउसिंग बोर्ड की रचना राज्यपाल ने की और दूसरे ट्राइबल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की रचना उन्होंने की है। मैं आशा करता हूं कि इन दो एजेंसियों के द्वारा वहां की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को लाभ होगा। लेकिन, श्रीमन्, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो हरिजन हैं, उनका सवाल केवल आर्थिक सवाल ही नहीं उनका मुख्य जो सवाल है वह शिक्षा का सवाल है और गुजरात में शिक्षा की क्या स्थिति है। खास कर के जहां पर वन्य प्रदेश हैं, जहां पर आदिवासी बस्तियों का

बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां पर महात्मा गांधी के नाम पर नई तालीम की संस्थायें चलती हैं, वहां क्या सिखाया जाता है। कृषि-विद्या सिखाई जाती है, वस्त्र-विद्या सिखाई जाती है, कुछ गौ-पालन का काम चलता है, खेती-बारी करवाई जाती है लेकिन वहां टर्नर, फिटर, मोटर इंजीनियर, प्राइमरी इंजीनियर, बढ़ई का काम, लोहे का काम यह नहीं सिखाया जाता, फलस्वरूप एक बहुत बड़ी संख्या में इन पिछड़ी हुई जातियों की सन्तान आज के जमाने के कदम के साथ अपने कदम नहीं मिला पाये हैं। वह स्वावलम्बी बन नहीं पाए। खेती तो उनका जन्म का पेशा है, उसको वह जानते हैं और वस्तु विद्या सिखाने से भी क्या फायदा होगा जब कि मिलें घंटे भर में सैकड़ों यार्ड कपड़ा निकाल देती हों, उस समय केवल चर्खा चलाने और कपड़ा बुनने के जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, इनसे उनकी क्या सेवा होगी जो गरीब लोग हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा।

श्रीमन्, एक आमतौर पर राय बनी हुई है बुनियादी शिक्षा जो है वह आदिवासियों के लिए हो, एक विशिष्ट शिक्षा के स्थान पर जो गुजरात में है। आम जनता का उसमें इतना चाव रहा नहीं, इतनी दिलचस्पी है नहीं। इसलिए मैं इस सदन में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में टर्नर, फिटर मोटर मैकेनिक, प्राइमरी इंजीनियरिंग, ऐसे टेक्निकल विषयों को जल्द से जल्द दाखिल करें ताकि उनको कुछ काम मिले और कुछ उद्योग की शिक्षा उनको मिल जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े रह सकें, अपनी रोजी कमा सकें, स्वावलम्बी बन सकें, जो महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त थे वे पूरे होते नहीं तभी आज ये लोग चरवाहे बन कर गायें और मवेशियां चरा रहे हैं।

इसके बाद श्रीमन्, मैं एक बात और रखना चाहता हूं। जंगलों में पंचमहाल की, भीलों की और डांग के कोटवालिया इत्यादि जो आदिम जातियां हैं। जो चाहती हैं अपने बांस उद्योग के लिए बांस ले सकें, सरकार के कानून कुछ ऐसे हैं कि उनको बांस मिलता नहीं। उनके पास कोई जमीन तो है नहीं, उनके पास आय के कोई और दूसरे साधन भी हैं नहीं। ऐसे समय पर उनको हमेशा के लिए एक पास दिया जाए ताकि वे हमेशा बांस ले सकें—आराम से और सरलता से और अपना उद्योग कर सकें और उसके द्वारा वे अपना जीवन-यापन कर सकें। साथ ही जो वन्य प्रदेश में रहते हैं उनके वास्ते जो जो भी, विशेष रूप से जो लकड़ियों के बारे में कानून बने हुए हैं वे इतने पेचीदा हैं कि वह बेचारे अनपढ़ आदिम जाति के लोग कानून के चंगुल में फंसते रहते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खास कर ऐसे लोग जिनका जीवन निर्वाह बांस के उद्योग पर चलता है, उन को बड़ी आसानी और सरलता के साथ बांस मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Subramania Menon.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir, while discussing this Resolution on the continuation of President's role in Gujarat, we have to take into consideration some of the realities of the situation in Gujarat. A number of speakers have spoken about the progress being made by the State in the industrial, in the educational and oilier fields. But there is one sphere in which Gujarat is in dismal depths. You will be surprised to know this.

I have recently had an occasion to visit, that State and saw the most harrowing things the scheduled castes and scheduled tribes are suffering from. The indignities to which they are subjected, the harassment they are victims to and the humiliations they suffer from, have no parallel elsewhere in this country. It is a strange fact that a State in which Mahatama Gandhi was born, a State which is supposed to be very progressive, shows the worst kind of untouchability and such other practices, which should shame any citizen of this country.

Now, Sir, you will be surprised to know that in Gujarat there is still a sort of, what is called bonded slavery. There is a section of 50,000 families known as *halpathis,* and these *liolpathis* are nothing but slaves. Twenty-two years after

[Shri K.. Pi Subramania Menon] ihe Constitution is enacted, if we cannot gel rid of this slavery, what sort of progress we are making in tins country ? It is a shameful il tliat 50,000 families are still living under slavery as ihe bonded slaves of the zamindars in the districts of Broach and Surat in the State of Gujarat. And what does this Governmen! do? We have had all sorts of sanctimonious Congressmen ruling ihe State.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh : Whal do these fifty lakhs do ?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : They are called *hiilpalhis.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Whal do they do ?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: They are cultivators in the sense tliat they live under the landlords and they are indebted to them and they have If) work for the landlords. They have absolutely no independence of their own. And do you know, Sir, what is the wage they get ? Their wage ranges from 60 naye Paise to 150 naye Paise. This is the sort of progress which the State has made. Of course it has made some progress, some of the big fellows have becom* richer and a iot of industries have sprung up and a few *banias* are making a lot of money out of it. But a large percentage of tire rural population, especially the landless labourers, the *Harijans* and the *Adivasis* are the worst sufferers. Then, Sir, is the problem of their indebtedness ; I shall give only one or two instances. Wherever there has been the mixed population of *Advises* and the plains people, the *Advises* have losl the land. Wherever the *Adivasis* themselves constitute the *panchayat,* and all, they have been able to withstand ihe onslaught of the plains people. But where there has been a mixed population and *the panchayat* lias been dominated hy the plains people, they have lost their land. Tn the Naswadi taluka for example. 1500 acres ol land have been alienated by the moneylenders for a paltry sum of Rs. 1,50,000, which means Rs. 75/-per acre. The *Adivasis* were thus cheated. They arc given paltry sinus in times of some sort of famine or when there is no work, as loans. They are given some grains nnd ;ill. and the moneylenders charge 150 to 200 per cent as inteiest on these things. This goes on accumulating and slowly ihrir lands are lalscn awav.

Then Sir. it is being said that a lot of land is being allotted to the *Adivasis* and the *Harijans* Bui what are the facts ? The facls are that, even where the Collector bas allotted some lands, the *panchayati* institutions, which are controlled by the landlords and the *thakurs,* they set apait these lands as grazing lands, and rot a cent of land is given to the *Hetijians* and l he *Adivasis.* The Collector issues orders that such and such a plot of land is given to so and so, luil the order is never given effect to, and the *Adivasis* and the *Harijans* do not get even a cent of land.

Then, Sir, you will be surprised to know that the most blatant exhibition of untouchability exists in Gujarat, the land of Gandhi. You will be surprised also to know that Porbunder, where Gandhi was born, is the worst place for untouchability. And they arc the *bhaktas* of Gandhiji. Such a hypocritical folk I have never seen anywhere in the world, people who call themselves Congressmen. AU of them are *G&rAhi-blwktas.* Anybody in Gujarat, any Congressman, they all salute Gandhiji, but they practise untouchability tn ihe most blatant and unashamed manner.

SHRI SURESH J. DESAI : May I interrupt my friend for a minute ? He seems ro be completely out of date.

SHRl K. P. SUBRAMANIA MENON : I am not out of date.

SHRI SURESH J. DESAI : Please listen.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Why should I listen to you now ? Please sit down and listen to me.

SHRI SURESH J. DESAI : The Deputy (Ihairman 1ms given me the time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not given you permission to interrupt him. Please (In not interrupt him.

SHRI SURESH J. DESAI: The hon. Member is completely out of date. He is speaking of things which were perhaps prevailing ten vear back.

•

SHRI K.P. SUBRAMANIA MENON : You read the upon of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes and *know* the facts ior yourself.

SHRI SURESH J. DESAI: Tlie *halpathi* system was prevailing some leu years bark, and the system is more or less extinguished now. Then the hon. Member speaks of untouchability being in the worst form in Gujarat. Perhaps he has nol visited other parts of the countiy. Yon will see tbat the worst untouchability is ihere in your State.

SHRIK P. SUBRAMANIA MENON: 1 understand the spirit—we must have it better.

SHRI SURESH J. DESAI : Untouchability is a malady all over ihe country. It is not thai it is there only in Gujarat and other Slates do not have il. Il is prevalent all over the country and we have to try to remove it, we are trying to remove it as far as possible.

So many other matters he lias mentioned'
which are completely irrelevant. He is out ol" date by ten years.

SHRI JOACHIM ALVA (Nominated) : My hon. friend forgets that the Jana Sangh carried ofTa lot of votes in Gujarat ou account of the cow agitation.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Mr. Desai unfortunately lives ten years back ; he lives ten centuries back. Whatever has been said is according to the Reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner of the last few years, and how do you say I am out of dale? In any case, I have visited Gujarat only last month.

In other States there is untouchability definitely, but there is a sly manner of doing it, they may do it in private homes. But very rarely do people practise it blatantly, publicly and unashamedly in public places. In Gujarat for example, in the Mehsana district, in the district headquarters town, there are two restaurants—Rajputana and Iqbal restaurants. You will be surprised to know—I went and saw and I felt ashamed—that the *Harijans* have to sit on the road side. They keep separate posts for them. They have to give them by washing them themselves, go to the shop, get the tea, come back and sit there and drink it. And the district authorities do not do anything about it. I'his is (he case, I am told, everywhere in Gujarat, including Rajkot. Well, I have seen it.

Another instance is in the Rajpipla municipality where one ol the *bania* girls fell in love w ith a *Harijan* boy. She was employed as a teacher in that municipality and that *Harijan* boy was employed in some Government office. There all the Government and public services are being used to victimise people who do not practise untouchability. It so happened that the girl was dismissed from her teacher's job in the Rajpipla municipality and that girl has not got a job just because she mar.-ied that *Harijan* boy. Not only that she is dismissed from her job—a job for which the State pays the money— but also she is ostracized by her own community and other communities. This is the most backward Staie.

The lasi thing is about the Panchayati Raj institutions. These Panchayati Raj institutions are a curse to the *Harijans* anj *Adivasis.* The powers vested in these panchayats are being used relentlessly to oppress the *Harijans* and *Adivasis.* Unless the Government does something to safeguard ihe interests of the *Harijans* against the depredations of these Panchayati Raj institutions, these things will become much worse in Gujarat.

SHRl F. H. MOHSIN: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very much thankful to the Members who have taken part in the debate and who have also given very useful suggestions. The lady-Member who spoke first went in detail about the various achievements made by the Government and also the work to be taken up under the several heads. Sunv: of my friends have laid stress on the state of affairs as regards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State of Gujarat. Sir, they constitute, about one-fifth of the total population in Gujarat. The Scheduled Tribes are said to be nearly 13.35 per cent of the total population and the Scheduled Castes account for 6.63 per cent but their economic condition has not remarkably impoved in spite of the Five Year Plans and so many measures that the State Government had taken so far. The State Government are now taking more measures in ihis direction. They intend io set up a Tribal Development Corporation which will enable the Government to take measures for social and economic amelioration of the Scheduled Tribes. They want to set up an authorised capital of Rs. 5 crores and bi ing forward a Bill in this respect. This may go a long way in improving the conditions of the Scheduled Castes and the

[Shri F. H, Mohsin] Scheduled Tribes. Over and above that, the State Government wants to establish a Rural Housing Board to accelerate the tempo of house-building for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the whole State. There has not been a separate Rural Housing Board ior house-building activities specially intended for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Now they are intending to set up such a Board to see that most of the houseless *Harijans, i.e.* the Scheduled Castes and Schedu'ed Tribe population get housing facilities.

Mr. Subramania Menon has stated about the severity of tlie untouchability problem in Gujarat. Sir, in spite of many meausres that have been taken to remove untouchability, it is really a matter of concern for the Government and for all of us to see that even at the present moment untouchability prevails in some parts of the country. It may be a matter of degrees in several States, but we cannot altogether say that untouchability has been removed. I do not say that no work has been done in this direction. There has been a marked improvement in this direction. What the situation was about 20 or !0 years back_ is notnow at present. Untouchability has been removed to a large extent and at the same time we cannot achieve more in this direction by passing only legislations or by making the penalties more severe. This could achieved by social workers, by educating the people on the eivils of untouchability. I think the social workers and the people at large can do a lot in removing untouchability rather then passing more and more laws in this respect. Sir, 1 do hope that the people will think in this prospective and see that this social evil which has been a black mark on all the Indians disappears sooner than what we expect.

Sir, in this brief period, I am very glad to state that the State has made remarkable progress. In the micl-term appraisal of the State's resources, it has been revealed that the Slate's resources have gone up by Rs. 45 crows, j. *e.* from Rs. 455 crores they have gone up to Rs. 500 crores and additional resources have also been added. They want to raise the size of the Plan to Rs. 500 crores instead of Rs. 455 crores. Various achievements have also been made in the case 3 P. M.

of food output and the irrigation facilities that have been provided. In the Industrial sector also so many licences have been given ar.d so many expansions have been assented to. There has been a marked improvement in the development plans of Gujarat State and I am sure that the House will appreciate whatever has been done in this short span of President's Rule. As I have already stated the Government of India wants a popular and democratic rule there as early as possible as we want it elsewhere too. As I have already announced we propose to hold the election in Gujarat also in the third week of February and we expect that a popular Ministry would come up and continue this development work in the future also. Hence I would appeal to the House to accept the Resolution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is—

> "That it is House approves the continuance in force of the proclamation isssued by the President on the 13th May, 1971 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Gujarat, for a further persod of six months witli effect from the 21st December, 1971."

The motion was adopted.

DISCUSSION ON THE PRIME MINISTER'S STATEMENT *RE* HER TOUR OF FOREIGN COUNTRIES

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, I raise a discussion on the statement made by the Prime Minister in the Rajya Sabha on the 15th November, 1971, about her tour of Belgium, Austria, the United Kingdom, the United States of America, France and the Federal Republic of Germany.

Sir, we are discussing the statement the Prime Minister made on her foreign tour in this House but since then much water has flown down the bridge and I think the situation is far more serious today then when the statement was made in the House. But still since we have to discuss the statement, I should like to make some observations about what she said by way of giving an account of her achievements or lack of achievements which of course is not mentioned in her statement in the House. We were also, Sir, keenly watching the results of the Prime Minister's talks with the leaders of the Government of the I western countries she visited. Wc had never